शोध मंथन Vol. XIV No.III July-Sep. 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.870 (SJIF)

षहरीकरण :– कारण, दुष्प्रभाव एवं सरकारी प्रयास

प्राप्तिः 29.08.2023
स्वीकृतः 17.09.2023

69

सीमा खडगावत
एसिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
मांगीलाल भागड़ी पी०जी० कॉलेज, बीकानेर राजस्थान
ईमेलः *seemaswami1984@gmail.com*

सारांश

दुनियां में बढ़ते औद्योगिकीकरण और विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शहरीकरण की प्रवृति देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है। इसके पीछे शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन व अन्य चमक–दमक या रोज़गार की तलाश में आने की मजबूरी कही जा सकती है। यद्यपि किसी देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उस देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का प्रतीक होता है परन्तु इसके साथ ही यह शिक्षा, स्वास्थ्य, आय व रोजगार, यातायात व संचार की सुविधाओं का अभाव, जल, थल एवं वायु प्रदूषण तथा अनेक प्रकार की चोरी, डकैती, हत्याऐं, बलात्कार, भ्रष्टाचार, हड़तालें, वेश्यावृत्ति जैसी समस्याऐं भी समेटे हुए है, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक अव्यवस्था व अराजकता को बढ़ावा मिलता है। प्रस्तुत शोध पत्र में शहरीकरण किस प्रकार से आर्थिक विकास का प्रतीक है? किन कारणों से शहरीकरण बढ़ रहा है? शहरीकरण के क्या–क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं तथा शहरीकरण से उत्पन्न समस्याओं पर नियन्त्रण करने की दिशा में सरकार द्वारा किन–किन योजनाओं को चलाया जा रहा है? यहाँ पर इन सब महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य बिन्दु

औद्योगिकीकरण, पलायन, भ्रष्टाचार, शहरीकरण।

आज दुनिया के सभी देशों में शहरीकरण की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। शहरीकरण का विस्तार विशेष रूप से औद्योगिक क्रान्ति के बाद से शुरू हुआ है। विकास प्रक्रिया में उद्योग धन्धों की स्थापना की वजह से यहाँ पर लोगों को रोज़गार व आय के अवसर प्राप्त होते हैं। अतः यहाँ पर काम करने वाली मानव शक्ति का संकेन्द्रीकरण होने से शहर बस जाते हैं।

इस प्रकार कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों का व्यापार, उद्योग एवं निर्माण कार्यों के लिए शहरों में जाकर रहना व काम करना शहरीकरण कहलाता है।

भारत की जनगणना, जनसांख्यिकी (आबादी की विशताएं), आर्थिक आंकलनों, साक्षरता एवं शिक्षा, आवास और घरेलू सुविधाएं, शहरीकरण, जन्म और मृत्यु दर आदि पर जानकारी का सबसे अधिक विश्वसनीय स्त्रोत है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। यह जनगणना

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (जनगणना महापंजीयक) और जनगणना आयुक्त श्री सी० चंद्रमौली के मार्गदर्शन में की गयी थी।

2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। गांव, कस्बा और वार्ड स्तर के प्राथमिक आंकड़ों का यह एकमात्र स्त्रोत है। यह केन्द्र और राज्य सरकारों को योजना एवं नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, विद्वान, व्यापार जगत के लोग, उद्योगपति और कई अन्य इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग करते हैं।

जनगणना 2011 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं–

1. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या	35
2. जिलों की संख्या	640 (वर्ष 2001 से 47 ज्यादा हैं)
3. शहरों की संख्या	7,933 (वर्ष 2001 से 2772 ज्यादा हैं)
4. गांवों की संख्या	6,40,930 (वर्ष 2001 से 2342 ज्यादा हैं)
5. कुल आबादी	1,21,05,69,573 (68.8% शहरी और 31.2% ग्रामीण)
6. शिशु लिंगानुपात (0.6 वर्ष)	919 (ग्रामीण 923 और शहरी 905)
7. लिंगानुपात	940 महिलाएं/1000 पुरुष
8. आबादी का घनत्व	382 व्यक्ति/वर्ग किसी
9. वर्ष 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि	17.64%
10. साक्षरता दर	कुल आबादी का 74.04%
11. भारत में दुनिया की कुल आबादी है–	17.5%
12. भारत की आबादी अब, इन देशों की संयुक्त आबादी से अधिक है	टमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश
13. सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्यद्वीप है	64,429 व्यक्ति
14. शीर्ष पांच शिक्षित राज्य हैं–	1. केरल 94.00% 2. लक्ष्यद्वीप 91.85% 3. मिजोरम 91.33% 4. गोवा 88.70% 5. त्रिपुरा 87.22%
15. सर्वोच्च लिंगानुपात वाले– शीर्ष पांच राज्य	1. केरल 1084 2. पुडुचेरी 1037 3. तमिलनाडु 996 4. आंध्र प्रदेश 993 5. छत्तीसगढ़ 991
16. सबसे कम लिंगानुपात– शीर्ष पांच राज्य	1. दमन और दीव 618 2. दादर और नगर हवेली 774 3. चंडीगढ़ 818 4. दिल्ली 868 5. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 876

17. पांच सर्वाधिक घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश	1. दिल्ली 11,320 2. चंडीगढ़ 9,258 3. पुडुचेरी 2,547 4. दमन और दीव 2,191 5. लक्ष्यद्वीप 2,149
18. सबसे अधिक घनत्व वाले चार शीर्ष राज्य	1. बिहार 1,106 2. पश्चिम बंगाल 1,028 3. केरल 860 4. उत्तर प्रदेश 829
19. भारत के शीर्ष चार सबसे अधिक आबादी वाले राज्य हैं	1. उत्तर प्रदेश 199,281,477 (16.49%) 2. महाराष्ट्र 112,372,972 (9.289%) 3. बिहार 103,804,637 (8.589%) 4. पश्चिम बंगाल 91,347,736 (7.559%)
20. भारत के सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश	1. चंडीगढ़ 1,054,686 (0.099%) 2. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 379,944 (0.039%) 3. दादर और नगर हवेली 342,853 (0.039%) 4. दमन और दीव 242,911 (0.029%) 5. लक्ष्यद्वीप 64,429 (0.019%)

भारत मे शहरीकरण

कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात शहरीकरण को बताता है–

$$\text{शहरीकरण} = \frac{\text{शहरों में रहने वाली जनसंख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

भारत में तेज गति से बढ़ती जनसंख्या के साथ ही लोगों की शहरीकरण की प्रवृत्ति को भी तीव्र गति से बढ़ावा मिला है। 1901 में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 11% हिस्सा शहरों में निवास करता था। जो अब बढ़कर 33 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है अर्थात् 120 वर्षों मे शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या तीन गुणा बढ़ गई है।

- भारत में 1901 से 1913 की अवधि के दौरान शहरीकरण 10.84% से बढ़कर 12% हो गया, सिर्फ 1.16% की नाममात्र बढ़ौतरी रही थी। इसका प्रमुख कारण इस अवधि में पड़ने वाले अकाल व महामारियों की वजह से कुल जनसंख्या में भी केवल 4 करोड़ की वृद्धि होना है।
- 1931 से 1961 की अवधि में शहरीकरण में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली है यह लगभग 6% की बढ़ौतरी थी अर्थात् 1931 मे 12% से 1961 में 18% हो गई।
- 1961 से लेकर 1991 तक की अवधि के दौरान यह 18% से बढ़कर 25.7% हो गई। यह लगभग 8% के आस–पास रही।
- 1991 से 2011 तक के तीन दशको में यह 25.7% से बढ़कर 31.2% हो गई है अर्थात् 5.5% की वृद्धि दर रही।

2020 में शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का हिस्सा कुल जनसंख्या का लगभग 33% है अर्थात् एक–तिहाई जनसंख्या अब शहरों में रहती है।

भारत में बढ़ते शहरीकरण के कारण

भारत में सन् 1901 में कुल जनसंख्या का लगभग 11% हिस्सा शहरों में निवास करता था। 1961 में अर्थात् 60 वर्षों में यह बढ़कर 18% के लगभग हो गया। परन्तु अगले 60 वर्षों, 2011 में यह 31.2% हो गया अर्थात् पहले 60 वर्षों में 7% बढ़ौतरी और अगले 60 वर्षों में यह बढ़ौतरी 14% के लगभग दर्ज की गई है। इस प्रकार आंकड़ों को देखकर कह सकते हैं कि भारत में शहरीकरण को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। इसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं:–

1) औद्योगिकीकरण

शहरीकरण और औद्योगिकीकरण में प्रत्यक्ष सम्बन्ध पाया जाता है अर्थात् औद्योगिकीकरण बढ़ेगा तो शहरीकरण भी बढ़ेगा। किसी स्थान पर बड़े–छोटे उद्योगों की स्थापना से वहां पर लोगों को अनेक प्रकार के रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं जिससे लोग यहां पर आकर बस जाते हैं।

2) कृषि पर बढ़ता जनसंख्या दवाब

जनसंख्या वृद्धि से परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने से भूमि के उपविभाजन एवं विखण्डन की समस्या बढ़ती है जिससे भूमि के छोटे–छोटे आंकड़ों पर कषषि कार्य करना लाभदायक नहीं रह जाता है। दूसरे हमारी कृषि मानसून पर निर्भर करती है अतः सूखे की स्थिति में किसान की हालात दयनीय हो जाती है और वे कषषि से विमुख होकर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर रूख कर लेते हैं।

3) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की कमी

एक तरफ तो कषषि अब लाभकारी व्यवसाय नहीं रहा है, दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, बिजली, यातायात एवं अन्य आधारभूत ढ़ांचे का अभाव पाया जाता है जिससे वहां पर किसी प्रकार के कुटीर और लघु उद्योग लगाना सम्भव नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी का अभाव होना भी एक कारण है।

4) बुनियादी सुविधाओं का होना

शहरी क्षेत्रों में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के साथ–साथ यातायात एवं संचार की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर होती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी परिवार आर्थिक रूप से सम्पन्न हो जाते हैं वे इन सुविधाओं और आरामप्रद जीवन के लालच में शहरों में प्लाट या फ्लैट खरीद कर वहां पर रहने लग जाते हैं।

5) शिक्षा व रोजगार के अवसर

शहरी क्षेत्रों में उद्योग, व्यवसाय व व्यापारिक क्रियाओं की वजह से लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाता है। दूसरे देश के बड़े और उच्च शिक्षण संस्थान शहरों में ही होते हैं सो ग्रामीण इलाकों से विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते हैं और बाद में रोजगार भी प्राप्त करके शहरों में ही निवास करने लग जाते हैं।

6) उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण

1991 के बाद से आर्थिक उदासीकरण की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित लघु व कुटीर उद्योग धंधे लगभग चौपट हो गये। इससे लोग बेरोजगार हो गये और वे रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन को मजबूर हो रहे हैं।

दूसरे वैश्वीकरण के कारण देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश हो रहा है। इन कम्पनियों ने गुड़गांव, नोएडा, बंग्लौर, हैदराबाद, पूणे, मैसूर जैसे बड़े–बड़े शहरों में अपने कार्यालय खोल रखे हैं। जिसमें लाखों की संख्या में देश के युवा कार्य करते है और स्वभाविक है कि यहाँ काम करने आएंगे तो रहना भी यही होगा। इससे भी शहरी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।

उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त सुरक्षा की भावना व उच्च जीवन स्तर की लालसा जैसे कुछ कारण है जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर खींच कर लाते हैं। संक्षेप में, बढ़ते शहरीकरण के पीछे तीन प्रमुख कारण कहे जा सकते हैं– पहला, जनता का शहरी सुविधाओं के प्रति आकर्षण का होना। दूसरा, कुछ लोग की आर्थिक व सामाजिक मजबूरियां होती हैं तथा तीसरे किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शहरों की ओर पलायन है।

षहरीकरण के प्रभाव

जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार शहरीकरण भी जैसे एक तरफ लोग की आय, रोजगार व जीवन स्तर में सुधार लाता है तो दूसरी तरफ पर्यावरणीय, स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा अन्य सामाजिक व नैतिक समस्याऐं भी पैदा होती हैं। इसका वर्णन हम निम्नलिखित दो भागों में कर सकते हैं:–

(A) शहरीकरण के लाभ

(B) शहरीकरण की हानियां

(A) शहरीकरण के लाभ

i) आर्थिक विकास

शहरों में उद्योग व अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं इससे लोगों की आय, उपभोग, बचत, निवेश तथा पूंजी निर्माण शक्ति में बढ़ौतरी होती है जो और आगे उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है।

ii) कृषि क्षेत्र को लाभ

ग्रामीण इलाकों से जनसंख्या शहरों की ओर जाने से कृषि भूमि पर दवाब में कमी आती है। जिससे प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन में बढ़ौतरी होती है और किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार सम्भव होता है।

iii) उच्च जीवन स्तर

शहरी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई की अच्छी सुविधाऐं मिलने से उनकी जीवन प्रत्याशा आयु में वृद्धि सम्भव हो पाती है। इससे उनकी कार्य क्षमता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कारक होता है।

iv) सोच में बदलाव

गाँव से लोग शहरो में आकर वहां की संस्कृति से प्रभावित होकर, अपने पुराने रूढ़िवादी तथा अन्धविश्वासी दृष्टिकोणों को छोड़ पाते हैं, जो कि उनकी आर्थिक प्रगति में बाधक थे। शिक्षा की वजह से उनका दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक और तार्किक बनता है जो आर्थिक विकास में सहायक होता है।

v) शहरीकरण की हानियां

शहरीकरण से जहाँ एक ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, आय व रोजगार में वृद्धि से देश का आर्थिक विकास सम्भव होता है वही दूसरी तरफ अनियोजित एवं अनियन्त्रित शहरीकरण से बहुत सारी समस्याऐं भी पैदा होती हैं। जिनका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

vi) बुनियादी सुविधाओं में कमी

शहरों में जनाधिक्य होने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात व संचार सुविधाओं की माँग को देखते हुए उस अनुपात में यह सब उपलब्ध नहीं हो पाता है।

vii) रोजगार का अभाव

जिस तेज गति से शहरों में लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जिससे बेरोज़गारी व गरीबी को बढ़ावा मिलता है।

viii) ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुछ काबिल, सक्षम एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं वे शहरों में चले जाते हैं इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचती है। दूसरी ओर इन लोगों को शहरों में भी सही रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे मानवीय संसाधनों का अपव्यय होता है।

ix) पर्यावरण प्रदूषण की समस्या

शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण, यातायात के साधनों व सीवेज व्यवस्था पर अधिक भार पड़ता है परिणामस्वरूप ध्वनि और जल प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में फैक्ट्रियों की भी अधिकता पाई जाती है जो वायु प्रदूषण को जन्म देती है।

x) अपराधों की संख्या मे बढ़ौतरी

शहरों में बढ़ती हुई आबादी के साथ–साथ ही चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, हड़ताल, जुआ, वेश्यावृत्ति व शराब पीने की घटनाओं में वृद्धि होती है जिससे सामाजिक अव्यवस्था व अराजकता फैलती है।

मलिन बस्तियां

शहरी क्षेत्रों जहाँ एक तरफ बड़ी ऊंची–ऊंची इमारतें, सुन्दर एवं आलीशान बंगले देखते हैं तो दूसरी तरफ इनके आजू–बाजू में बनी हजारो की तादात में झुग्गियां भी किसी से छुपी नहीं रहती हैं। ये सामान्यता ग्रीन बेल्ट, रेलवे लाईनों, सड़कों व नहरों के किनारे बनी हुई होती हैं तथा पूर्ण रूप से अवैध व गैर कानूनी होती हैं। देश मे वोट की राजनीति होने की वजह से कोई भी सरकार इनको हटाने का प्रयास नहीं करती है बल्कि इनको बढ़ावा देती है। इन बस्तियों में प्रायः दिहाड़ी मज़दूर और छोटे व्यवसायी रहते हैं। इनमें रहने वाले लोगों की संस्कृति, भाषा, धर्म, परम्पराऐं व रिवाज भले ही भिन्न–भिन्न हो परन्तु मुख्य कारक आर्थिक होता है जो इन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर देता है।

गरीबी व मजबूरी की वजह से ये मलिन बस्तियां जुआ, शराबखोरी, चोरी, वेश्यावृत्ति, बलात्कार जैसी असामाजिक गतिविधियों के अड्डे होते हैं। यहाँ पर बिजली व पानी चोरी जैसी घटनाऐं आम बात होती है। कुछ अपराधी एवं दबंग प्रवृति के लोगों द्वारा इन बेबस व मजबूर लोगों से अवैध वसूलियां भी की जाती हैं। इन लोगों का जीवन पूर्ण रूप से नरकीय होता है।

भारत के शहरों में लगभग 18% शहरी जनसंख्या इन मलिन–बस्तियों की झुग्गियों में रहती है। मुम्बई की मलिन बस्ती 'धारावी (दक्षिण मुम्बई) एशिया की दूसरी तथा प्रथम 'औरंगी' पाकिस्तान में कराची के निकट है। कोलकत्ता में बड़ा बाजार के आस–पास, चैन्नई में माऊंट रोड के उत्तरी भागों व पटना में सब्जी बाजार के पास ऐसी मलिन–बस्तियों की भरमार है।

षहरीकरण की समस्या से निपटने के लिए सरकारी प्रयास

हमारा शहरी विकास तन्त्र उतना अच्छा नहीं है जितना कि इसको होना चाहिए। इसके पीछे समुचित शहरी नीति का अभाव होना, अनुचित शहरी नियोजन, आर्थिक संसाधनों का अभाव, जवाबदेही एवं पारदर्शिता का अभाव तथा विभिन्न विभागों जैसे जन स्वास्थ्य, बिजली–पानी, तथा यातायात आदि के बीच असमन्वय का अभाव का होना है। इसलिए समुचित शहरीकरण के लिए पर्याप्त ढ़ांचे जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़कें, यातायात व संचार व्यवस्था, रोजगार, सफाई व शुद्ध पर्यावरण हेतु प्रबन्धन की आवश्यकता है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा जून तथा अगस्त 2015 में कुछ महत्वाकांशी योजनाओं का प्रारूप तैयार किया गया है। हम आशा करते हैं कि शहरीकरण में कुछ सुधार सम्भव होगा।

सरकार की प्रमुख योजनाऐं निम्न प्रकार से हैं :–

1. शहरी रूपान्तरण एवं नवीनीकरण अटल मिशन
2.. स्मार्ट शहर मिशन
3. '2022 तक सभी के लिए आवास' मिशन

1. शहरी रूपान्तरण व नवीनीकरण– अटल मिशन

25 जून 2015 को केन्द्र सरकार ने इस योजना को लागू किया है इसमें देश में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों व कस्बों में से 500 का चयन किया जाएगा तथा साथ ही प्रमुख नदियों, राजधानियों, पवर्तीय क्षेत्रों, द्वीपों और मुख्य पर्यटन स्थलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इन शहरों में पर्याप्त मात्रा में सड़कों, सीवेज व्यवस्था, बिजली–पानी, शिक्षा–स्वास्थ्य, यातायात तथा संचार व्यवस्था की जाएगी। ताकि यहाँ पर निवास करने वाले लोगो के जीवन की गुणवत्ता में सुधार सम्भव हो सके।

2. स्मार्ट शहर मिशन

27 अगस्त, 2015 को उपरोक्त योजना की तर्ज पर ही देश के अन्दर एक 'सिटी चैलेंज प्रतियोगिता' के आधार पर कुछ 100 शहरों का चयन किया जाएगा और प्रत्येक शहर को उसकी शहरी ढ़ांचागत व्यवस्था में सुधार के लिए प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी ताकि वित्तीय संसाधनों के चलते शहरवासियों को सीवेज, परिवहन, सड़कों व अन्य समस्याओं से जूझना न पड़े।

3. 2022 तक सभी के लिए आवास मिशन

शहरी आवास हेतु इस मिशन को 'प्रधानमन्त्री आवास योजना' का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिये अगले 7 वर्षों में 2 करोड़ आवासों का निर्माण किया जाएगा। ताकि इन लोगों को झुग्गियों और मिलन बस्तियों से निजात मिल सके और अपने नरकीय जीवन से निकल सके।

सार स्वरूप सरकार की ये सभी योजनाऐं बहुत अच्छी हैं बशर्ते कि इनका क्रियान्वयन ईमानदारी से किया जाए। सच कहे तो इन योजनाओं का 50% पैसा सही मायने में, उचित लाभार्थियों तक भी पहुंच पाए तो भी एक बड़ी बात होगी और योजनाऐं अपने लक्ष्य प्राप्ति को फलीभूत करती नज़र आएगी।

आगे क्या किया जा सकता है?

शहरीकरण से बढ़ती समस्याओं पर नियन्त्रण पाने के लिए हमें शहर के आकर्षण के प्रति लोगों की सोच बदलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रो में बिजली–पानी, शिक्षा–स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ाना होगा तथा साथ ही वहाँ रोज़गार के अवसर भी तलाशने होंगे ताकि शहरों में जनसंख्या का दबाव कम किया जा सके। इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास सम्भव हो सकते हैं–

- → ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करके उनके शहर की ओर पलायन को रोका जाए। मनरेगा इस दिशा में कारगर सिद्ध हो सकता है।
- → ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना होगा।
- → शहरों में स्थानीय नियोजन और सार्वजनिक उपयोगिता के जरिये उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।
- → शहरी स्थानीय निकायों को और वित्तीय शक्तियां प्रदान करनी होगी।
- → धारणीय, समावेशी तथा तीव्र संवर्षद्धि को प्रोत्साहित करना होगा।
- → राजकोषीय वितरण एवं विकास कार्यो हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था करना।
- → भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी पर नियन्त्रण हेतु ऑन–लाईन जैसी व्यवस्थाओ के जरिये पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा।
- → उपलब्ध भूमि एवं वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढ़ंग से प्रबन्धन करना होगा।

सन्दर्भ

1. अग्रवाल, ए०एन०., अग्रवाल, एस०के०. ''भारतीय अर्थव्यवस्था''. न्यू ऍज पब्लिकेशनः नई दिल्ली।
2. गुप्ता, एस०एन० ''जनांकिकी के मूल तत्व''. हिमालया पब्लिकेशन्सः नई दिल्ली।
3. मलैया, के०सी०., शर्मा, रमा. ''जनसंख्या शिक्षा''. अग्रवाल पब्लिकेशनः आगरा (यू०पी०)।
4. पुरी, वी०के०., मिश्रा, एस०के०. ''भारतीय अर्थव्यवस्था''. हिमालय पब्लिकेशन्सः नई दिल्ली।
5. साहू, वी०के०. ''पॉपुलेशन एजुकेशन''. स्ट्रीलंग पब्लिशर्सज प्राइवेट लिमिटेडः नई दिल्ली।
6. वांगु, एम०एल०. ''पॉपुलेशन एजुकेशन''. टण्डन पब्लिकेशन्सः लुधियाना (पंजाब)।